RNI No. RAJHIN/2001/05699

हैलो सरकार

जनता की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का एकमात्र समाचार-पत्र

www.hellosarkar.com

पल-पल की टी.वी. एवं रेडियो खबरों के लिए लॉन ऑन करें- www.hellosarkar.com

हैलो सरकार समाचार पत्र में नियमित पाठक बनने, समाचार की प्रति मंगवाने व विज्ञापन देने हेतु सम्पर्क करें
फोनः 0141-2202717
मोः 9214203182
वाट्सप नं. 9928078717

वर्ष-25 | अंक-266 | दैनिक प्रभात संस्करण | जयपुर, शनिवार 30 मई, 2026 | पृष्ठ-4 | मूल्यः 2.50

सुविचार

खुद का अपमान कराके जीने से तो अच्छा मर जाना है क्योंकि प्राणों के त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होता है पर अपमानित होकर जीवित रहने से आजीवन दुःख होता है।

-चाणक्य

तारीख पर तारीख का खेल खत्म

हैलो सरकार न्यूज

नईदिल्ली। देश के हाईकोर्टों में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसले (रिजर्व रखे गए) के लिए तारीख पर तारीख का इंतजार नहीं करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व फैसले सुनाने में देरी पर चिंता जताते हुए हाईकोटों के लिए बाध्यकारी गाइडलाइन तय की है। इसके तहत हाईकोर्टों को रिजर्व फैसला तीन माह में सुनाना होगा। साथ ही जमानत आवेदनों पर सुनवाई के बाद उसी दिन या अधिकतम अगले दिन आदेश सुनाना होगा और वेबसाइट पर इसे अपलोड करना होगा।

जमानत मिलने वाले व्यक्ति को उसी दिन या अगले दिन जेल से छोड़ना अनिवार्य होगा। देश के चीफ जस्टिस (सीजेआइ) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने झारखंड हाईकोर्ट में आपराधिक अपीलों में सुनवाई के बाद दो-तीन साल तक फैसला लंबित रहने संबंधी केस की सुनवाई के बाद देश भर के लिए गाइडलाइन जारी की।

त्वरित न्याय के लिए विशेष शक्ति का उपयोग

बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत संपूर्ण न्याय के लिए मिली शक्ति का उपयोग करते हुए दिशा-निर्देश तय किए। बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट प्राथमिक संस्थाएं हैं जहां हजारों लोग प्रतिदिन राहत पाने के लिए आते हैं। निर्णयों में देरी न्यायपालिका में जनता के विश्वास को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। बेंच ने स्पष्ट किया कि यह निर्देश किसी भी जज या न्यायिक संस्था पर लांछन लगाने के लिए नहीं है।

ये दिशा निर्देश

हाईकोर्ट निर्णय रिजर्व रखने के तीन माह में तर्कसंगत निर्णय सुनाने का प्रयास करेगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नियमित व अग्रिम जमानत के मामलों में ज्यादा तत्परता बरतें।

जमानत मामलों में मानक तौर पर उसी दिन आदेश सुनाएं व अपलोड करें, यदि निर्णय रिजर्व है तो अगले दिन सुनाकर वेबसाइट पर अपलोड करें।

जमानत देने या सजा निलंबन के आदेश सुनाने के बाद तत्काल जेल अधिकारियों को सूचित करें, संबंधित व्यक्ति उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा हो। अनुपालन रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश हो।

यदि बेंच को विस्तृत व तर्कपूर्ण निर्णय सुनाने में देरी से दोनों पक्षों को कठिनाई है तो निर्णय का मुख्य भाग अदालत में सुनाकर विस्तृत निर्णय सात दिन या विशेषि स्थिति में 15 दिन में वेबसाइट पर अपलोड हो।

खुली अदालतों में सुनाया गया विस्तृत निर्णय 24 घंटे में वेबसाइट पर अपलोड हो।

हाईकोर्ट वेबसाइट में जरूरी बदलाव करें। हर माह के अंत में चीफ जस्टिस को गोपनीय रिपोर्ट पेश हो जिसमें उस माह के सभी लंबित रिजर्व फैसलों का विवरण हो। जहां निर्णय दो माह से लंबित है इसकी सूचना संबंधित बेंच को भी दी जा सकती है।

यदि तीन माह में रिजर्व निर्णय नहीं सुनाया जाता है, तो रजिस्ट्रार जनरल आदेश के लिए चीफ जस्टिस (सीजे) के सामने मामला रखेंगे। सीजे संबंधित बेंच को यह सूचित करेंगे। फिर भी दो सप्ताह में फैसला नहीं सुनाया जाए तो सीजे मामले को दोबारा सुनवाई के लिए अन्य बेंच को सौंप सकेंगे जो सुनवाई कर शीघ्र निर्णय सुनाए। यदि रिजर्व निर्णय तीन माह में नहीं सुनाया जाए तो मुकदमे के पक्षकार अर्जी दाखिल कर सकेंगे जिस पर दो दिन में सुनवाई होगी।

यदि निर्णय रिजर्व रखने की तिथि से चार माह में नहीं सुनाया जाए तो मुकदमे के पक्षकार सीजे के समक्ष अन्य बेंच को मामला सौंपने का आवेदन कर सकेंगे।

उच्च न्यायालयों को अपनी वेबसाइट पर यह भी दर्शाना होगा कि फैसला कब सुरक्षित रखा गया, मुख्य भाग कब सुनाया गया और तर्कयुक्त निर्णय कब अपलोड हुआ।

हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल इन दिशा-निर्देशों को सीजे के समक्ष रखेंगे ताकि नियमों में जरूरी बदलाव किए जा सकें।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश- 3 महीने में सुनाने होंगे रिजर्व फैसले

शहीदों की मूर्तियां लगाकर ही रहेंगे-बैसला

हैलो सरकार न्यूज

सवाईमाधोपुर। गुर्जर आरक्षण आंदोलन में जान गंवाने वाले युवकों की याद में आयोजित भगवान देवनारायण राष्ट्रीय महोत्सव शुक्रवार को आस्था, श्रद्धा और शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बन गया। कुशालीदर्रा शहीद स्मारक पर हजारों की संख्या में समाज के लोग जुटे। कार्यक्रम में पहुंचे गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक विजय बैंसला ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए बड़ा ऐलान किया कि आंदोलन में मारे गए लोगों की मूर्तियां कुशालीपुरा तिराहे पर स्थापित की जाएंगी। उनके इस ऐलान के बाद माहौल और गर्म हो गया।

तीन दिवसीय महोत्सव के दौरान कुशालीदर्रा शहीद स्मारक से लेकर हलौंदा मोड़ तक लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। समाज के लोगों ने विजय बैंसला का स्वागत किया और शहीदों के समर्थन में नारे लगाए। गुरुवार रात आयोजित भजन संध्या और शुक्रवार को दिनभर चली रामरसिया एवं पद दंगल पार्टियों की प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं को बांधे रखा। महिलाएं, युवा और बुजुर्ग बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुए।

एसपी ने संभाला मोर्चा

कार्यक्रम में बढ़ती भीड़ को देखते हुए सवाई माधोपुर का पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया। सुरक्षा के मद्देनजर कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। बाद में विजय बैंसला ने बोदल गांव पहुंचकर अधिकारियों से बातचीत की, जिसके बाद यातायात दोबारा शुरू कराया गया।

पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेय ने स्वयं भोमियाजी टेक पर मोर्चा संभाला और पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी। राष्ट्रीय राजमार्ग और कमलेश्वर महादेव मार्ग पर बैरिकेड्स लगाकर वाहनों की जांच की गई। इस दौरान समिति उपाध्यक्ष भूरा भगत, किसान संघ मंत्री लटूर सिंह गुर्जर, कर्नल बैंसला फाउंडेशन अध्यक्ष रंगलाल गुर्जर और पूर्व प्रधान गिर्राज गुर्जर सहित हजारों लोग मौजूद रहे।

मूर्तियों को लेकर बढ़ी हलचल

गुर्जर समाज लंबे समय से आंदोलन में मारे गए युवकों की मूर्तियां लगाने की मांग कर रहा है। समाज का कहना है कि आंदोलन में शहीद हुए लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। ऐसे में वे मूर्ति लगाने पर अड़े हुए हैं।

विजय बैंसला ने घोषणा की कि शनिवार को श्रद्धांजलि दिवस पर मूर्तियों का अनावरण किया जाएगा। वहीं समाज ने साफ कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो आगे आंदोलन भी किया जाएगा। विजय बैंसला के ऐलान के बाद प्रशासन की चिंता बढ़ गई है और अब सभी की नजर अगले कदम पर टिकी हुई है।

जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई-प्लेसमेंट एजेंसी संचालक 40,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

डॉ रामेश्वर सिंह, उपमहानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के सुपरविजन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एस.यू- प्रथम चौकी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत कौशिक के नेतृत्व में किया गया ऑपरेशन

हैलो सरकार न्यूज, जयपुर। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी एस यू प्रथम द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी अनिल कुमार, डायनेमिक मैनपांवर एण्ड सिक्योरिटी सर्विसेज जयपुर (प्लेसमेंट ऐजेन्सी) प्रोपराईटर को परिवादिया व सह परिवादी से रिश्वत राशि 40,000/- रूपये प्राप्त करने पर गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी एस.यू. प्रथम जयपुर में परिवादिया द्वारा आरोपी अनिल कुमार के विरूद्ध रिश्वत राशि मांगने की शिकायत प्रस्तुत की गयी। जिसमे बताया गया की परिवादिया को प्रति माह 6300/- रूपये का भुगतान आरोपी अनिल कुमार द्वारा पीएफ व ईएसआई की कटौती के पश्चात किया जाता रहा है।आरोपी अनिल कुमार प्रोपराईटर मैसर्स डायनेमिक मैनपांवर एण्ड सिक्योरिटी सर्विसेज जयपुर (प्लेसमेंट ऐजेन्सी) के प्रोपराईटर / संचालक द्वारा राज्य सरकार के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-द्वितीय से निविदा के अन्तर्गत डॉक्टर / एएनएम / जीएनएम / सफाई कर्मचारी का कार्य आदेश प्राप्त कर उक्त कार्य आदेश के अन्तर्गत परिवादिया को आयुष्मान आरोग्य मन्दिर गरुडवासी, चाकसू में संविदा

पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। आरोपी द्वारा परिवादिया के यूएएन नम्बर, पीएफ, ईएसआई उसकी एमप्लाई आईडी / सर्विस से लिंक करने (जोडने) के लिये 50,000/- हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा हैं।

दिनांक 21.05.2026 को परिवादी व सह परिवादी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान पाया गया की 40,000/- हजार रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिये सहमति प्रदान करना एवं सत्यापन के दौरान ही 5,000/- हजार रूपये की रिश्वत राशि सह परिवादी से प्राप्त की गयी एवं शंका होने पर आरोपी अनिल कुमार द्वारा वापस लौटते हुये एक साथ पुरी रिश्वत राशि देने के बारे में कहा गया।

जिस पर डॉ रामेश्वर सिंह, उपमहानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के सुपरविजन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एस.यू- प्रथम चौकी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत कौशिक के नेतृत्व में टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी को सह परिवादी से 40,000/- रूपये की रिश्वत राशि अपने हाथ से प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, एवं आरोपी के पास परिवादिया का कार्य लम्बित होना भी पाया गया।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक पुलिस एस.परिमला के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ एवं कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार पर सीएम भजनलाल शर्मा का वज्रप्रहार

हैलो सरकार न्यूज, जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्ट और लापरवाह अफसरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए साफ संदेश दे दिया है कि भ्रष्टाचारियों को शासन-प्रशासन में किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कड़े तेवर दिखाते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति पर ढाई वर्ष में एक आईएएस अधिकारी सहित 103 अधिकारियों को निलंबित किया है। वहीं, 6 अफसरों को सेवा से बर्खास्त और 11 भ्रष्ट अधिकारियों की आजीवन पेंशन पर रोक लगाई है। उन्होंने रिश्वत, ट्रैप, पद का दुरूपयोग, आय से अधिक संपत्ति प्रकरणों के 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति दी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत 37 अन्य प्रकरणों में भी कठोर कार्रवाई की है।

कोर्ट में दोषी साबित हुए तो सीधे बर्खास्तगी

रिश्वत, आय से अधिक संपत्ति और पद का दुरूपयोग करने पर अधिकारियों को न्यायालय में दोष सिद्ध होने के बाद तुरंत सेवा से निकाल बाहर किया गया। पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन विकास अधिकारी (सुवाणा, भीलवाड़ा) भरत प्रकाश मेघवाल, तत्कालीन कृषि उप निदेशक (झुंझुनूं) राजेश कुमार नैनावत, तत्कालीन सहायक आयुक्त भरतपुर (वित्त कर) महावीर सिंह आसीवाल, तीन चिकित्सा अधिकारी डॉ. राम मोहन सिंह चौहान (सीएचसी बिछीवाड़ा, डूंगरपुर), डॉ. मुरलीधर शर्मा (सीएचसी रामगढ़ पचवारा, दौसा) और डॉ. मनोहर लाल (सीएचसी रामगढ़, अलवर) को सेवा से बर्खास्त किया गया है।

जनता को मिलेगा साफ-सुथरा प्रशासन

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जो अफसर जनता के पैसे पर डाका डालेगा, उसकी न नौकरी रहेगी, न पेंशन और न ही कानून से बचने का कोई रास्ता। सरकार ने 11 अधिकारियों को भ्रष्टाचार सहित विभिन्न मामलों में आजीवन शत-प्रतिशत पेंशन रोक कर दण्डित किया है, जिनमें बनवारी लाल मीणा, आरएएस, तत्कालीन उप सचिव (नगर विकास न्यास, अलवर), डॉ. शिवनारायण यादव, तत्कालीन वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (सीएचसी, नीमराणा, अलवर), देवेन्द्र सिंह ढिल्लो, आरएएस, उप सचिव (नगर विकास न्यास, अलवर), मनोहर लाल सिसोदिया, तत्कालीन विकास अधिकारी (कपासन), तत्कालीन कनिष्ठ विशेषज्ञ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद कोठारी (सीएचसी मांडलगढ, भीलवाड़ा), डॉ. कल्पना श्रीवास्तव, तत्कालीन चिकित्साधिकारी, (गंगरार-चित्तौडगढ़), नृसिंह रेबारी, तत्कालीन सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी (प्रतापगढ़), सुरेश माथुर, तत्कालीन अधिशाषी अभियंता पीडब्ल्यूडी (जैसलमेर), महेन्द्र सिंह, आरपीएस, तत्कालीन वृत्ताधिकारी (सवाई माधोपुर), डॉ. लक्ष्मण दत्त शर्मा, तत्कालीन चिकित्साधिकारी (निवाई-टोंक) एवं डॉ. अविनाश कुमार शर्मा, तत्कालीन सहायक निदेशक, पशुधन विकास (बांसवाड़ा) शामिल हैं।

जनता के पीने के पानी से खिलवाड़ करने पर गई नौकरी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसते हुए एक और बड़ी कार्रवाई की है। पीएचईडी की अलवर प्रयोगशाला के वरिष्ठ रसायनज्ञ प्रदीप कुमार हजरती ने पेयजल के नमूनों की गुणवत्ता जांच में फर्जी रिपोर्ट तैयार की। मुख्यमंत्री ने ऐसे घोर लापरवाह अधिकारी को तत्काल सेवा से बाहर करने का निर्णय लिया। इसी तरह, हरिसिंह मीना (तत्कालीन एपीपी, एसीजेएम-4, कोटा) को एसीबी कोर्ट द्वारा सजा सुनाये जाने के बाद नौकरी से हटाया।

- और किस पर क्या कार्रवाई -

अनिवार्य सेवानिवृत्ति- डॉ. विलास राव गुल्हाने (तत्कालीन वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, झालावाड़)

आजीवन शत-प्रतिशत पेंशन रोकी- देशराज नूनिया (तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, आईजीएनपी मोहनगढ़, जैसलमेर)

अभियोजन स्वीकृति- देवी सिंह (तत्कालीन एसडीएम, डीग), डॉ. पवन कुमार जैन (तत्कालीन बीसीएमओ, लालसोट), मायालाल सैनी (तत्कालीन एक्सईएन पीएचईडी अलवर), राकेश चौहान (तत्कालीन एईएन पीएचईडी अलवर), गोपाल लाल कुमावत (तत्कालीन लेखाधिकारी, राज. जलप्रदाय एवं सीवरेज बोर्ड, जयपुर), राकेश सिंह (तत्कालीन एईएन पीएचईडी नीमराना), प्रदीप कुमार (तत्कालीन जेईएन पीएचईडी नीमराना), विशाल सक्सेना (तत्कालीन एक्सईएन पीएचईडी शाहपुरा), महेन्द्र प्रकाश सोनी (तत्कालीन एसीई विशेष परियोजना, अजमेर)

एक आईएएस सहित 103 अफसर निलंबित, 6 बर्खास्त, 108 प्रकरणों में दी अभियोजन स्वीकृति

राजमंदिर की गोल्डन जुबली पर खास तोहफा

हैलो सरकार न्यूज, जयपुर। विश्व में फेमस राजमंदिर एक जून को अपनी गोल्डन जुबली मनाएगा। इसका उद्घाटन 1 जून 1976 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने किया था। वर्ष 1976 में यहां पहली फिल्म 'चरस' लगी, जिसमें मुख्य भूमिका में धर्मेन्द्र देओल और हेमा मालिनी रहे। राजमंदिर के मैनेजर अशोक तंवर और इंचार्ज अंकुर खंडेलवाल का कहना है कि राजमंदिर की गोल्डन जुबली पर एक जून को सिने लवर्स को राजमंदिर में निशुल्क पांच फिल्में दिखाई जाएगी। इसके लिए टिकट बिक्री शुरू हो चुकी है।

राजमंदिर को लेकर आज भी लोगों का मानना है कि जब तक इसका दीदार नहीं कर लेते तब तक गुलाबी नगर की यात्रा अधूरी लगती है। इसकी खूबसूरती दिल में बस जाती है।

ये फिल्में दिखाई जाएगी

चुपके चुपके- सुबह 8 बजे
हम आपके हैं कौन- सुबह 11 बजे
राम तेरी गंगा मैली- दोपहर 3 बजे
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे- शाम 6:30 बजे
जिंदगी ना मिलेगी दोबारा- रात 10:30 बजे

वंदे-गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण एवं स्वच्छता गतिविधियों का जिले में हो रहा है व्यापक आयोजन

हैलो सरकार न्यूज, जयपुर। वंदे-गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के अंतर्गत शुक्रवार को जिले में जल संरक्षण, स्वच्छता एवं जनजागरूकता से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का व्यापक स्तर पर आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि अभियान के तहत जल स्त्रोतों के संरक्षण, स्वच्छता गतिविधियों, रिचार्ज संरचनाओं के निर्माण तथा जनभागीदारी को बढावा देने के लिए विभिन्न ब्लॉकों एवं ग्राम पंचायतों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

फागी ब्लॉक की ग्राम पंचायत भोजपुरा में आयोजित कार्यक्रम विशेष आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें सलोनी खेमका, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ने सहभागिता कर अभियान गतिविधियों का अवलोकन किया। कार्यक्रम के दौरान तालाब की साफ-सफाई, जल संरक्षण शपथ, कलश यात्रा, रिचार्ज शाफ्ट निर्माण एवं जनजागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विकास अधिकारी, जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। निदेशक ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए आमजन से वर्षा जल संचयन एवं जल स्त्रोतों के संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।

इसी तरह जमवारामगढ़ ब्लॉक की समस्त 30 ग्राम पंचायतों में पौधारोपण हेतु गड्ढा खुदाई, रिचार्ज शाफ्ट निर्माण, पशु खेलियों की साफ-सफाई तथा कार्यालय परिसरों में स्वच्छता अभियान संचालित किए गए। इन गतिविधियों में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय कार्मिकों सहित लगभग 2460 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

वहीं सांभर ब्लॉक की विभिन्न ग्राम पंचायतों में प्राचीन तालाबों, जोहडों एवं अन्य जल स्त्रोतों की साफ-सफाई एवं मरम्मत कार्य करवाए गए। ग्रामों में जल स्त्रोतों की मैपिंग कर उनकी साफ-सफाई सुनिश्चित की गई तथा मुख्य मार्गों, सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यालय परिसरों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु रिचार्ज शाफ्ट निर्माण एवं अन्य जल संवर्धन गतिविधियां भी आयोजित की गईं। इन कार्यक्रमों में लगभग 500 प्रतिभागियों ने सक्रिय सहभागिता निभाई।

इसी प्रकार किशनगढ़ रेनवाल ब्लॉक में भी जल संरक्षण एवं स्वच्छता से संबंधित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। जल स्त्रोतों की साफ-सफाई, स्वच्छता अभियान एवं जनजागरूकता कार्यक्रमों में लगभग 250 प्रतिभागियों ने भाग लेकर अभियान को सफल बनाया।

अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों, स्वयं सहायता समूहों, महिला समूहों, विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के माध्यम से जयपुर जिले में जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने तथा भावी पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों के संरक्षण हेतु प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं।

मोजिका रियल एस्टेट पर रेरा का शिकंजा

हैलो सरकार न्यूज, जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RAJ-RERA) ने घर खरीदारों के वित्तीय विधिक अधिकारों को मजबूती प्रदान करते हुए बड़ा और नजीर बनने वाला फैसला सुनाया है। रेरा ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी प्रोजेक्ट में प्रमोटर और खरीदार के बीच अंतिम विक्रय समझौता निष्पादित नहीं हुआ है, तो बुकिंग रद्द होने की स्थिति में बिल्डर अपनी मर्जी से कोई भी कटौती या जब्ती नहीं कर सकता। अथॉरिटी की सदस्य रश्मि गुप्ता ने आवंटी के पक्ष में फैसला देते हुए प्रमोटर M/s Mojika Real Estate & Developers Pvt. Ltd. को पूरी एडवांस बुकिंग राशि बिना किसी कटौती के वापस करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

मामले के विवरण के अनुसार, शिकायतकर्ता गिरिराज गुप्ता ने जयपुर स्थित ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट मोजिका लक्ष्मी विहार में फ्लैट नंबर 29 बुक किया था। इस फ्लैट की कुल कीमत ?14,00,000 तय की गई थी। आवंटी ने बुकिंग के समय 23 मई 2025 को एडवांस बुकिंग अमाउंट के तौर पर ?1,00,000 और अतिरिक्त ?1,185 का भुगतान बिल्डर को किया था। शेष राशि के भुगतान के लिए आवंटी ने बैंक से होम लोन के लिए आवेदन किया, लेकिन किन्हीं कारणों से बैंक ने लोन स्वीकृत करने से इनकार कर दिया। वित्तीय असमर्थता के चलते आवंटी ने बिल्डर से अपनी बुकिंग रद्द कर पैसा वापस मांगा, लेकिन बिल्डर ने राशि लौटाने में आनाकानी शुरू कर दी। थक-हारकर आवंटी ने रेरा का दरवाजा खटखटाया।

सुनवाई के दौरान प्रमोटर पक्ष की ओर से तर्क देने का प्रयास किया गया कि बुकिंग रद्द होने पर प्रशासनिक और बुकिंग नियमों के तहत कटौती की जानी चाहिए। हालांकि, रेरा अथॉरिटी ने रिकॉर्ड की जांच में पाया कि दोनों पक्षों के बीच केवल एडवांस बुकिंग की रसीदें थीं, और नियमों के तहत कोई औपचारिक या पंजीकृत %एग्रीमेंट फॉर सेल% (ञ्जस्) निष्पादित नहीं हुआ था। अथॉरिटी ने इस विधिक बिंदु को रेखांकित किया कि जब दोनों पक्षों के बीच कोई कानूनी अनुबंध (ञ्जस्) ही अस्तित्व में नहीं था, तो ऐसी स्थिति में रद्दीकरण पर पैसे काटने की कोई भी शर्त या नियम दोनों पक्षों पर सर्वमान्य रूप से लागू नहीं हो सकते। साथ ही, आवंटी द्वारा जमा कराई गई ?1,00,000 की राशि कुल फ्लैट कीमत के 10 प्रतिशत के विधिक मापदंड से भी काफी कम थी। अथॉरिटी ने न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों के तहत फैसला सुनाते हुए मोजिका रियल एस्टेट को आदेश दिया है कि वह आवंटी द्वारा जमा की गई कुल राशि ?1,01,185 बिना किसी भी प्रकार की कटौती या अर्नेस्ट मनी जब्ती के वापस लौटाए। चूंकि मामला आवंटी के स्तर पर बुकिंग रद्द कराने का था और एग्रीमेंट नहीं हुआ था, इसलिए इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं माना गया है। रेरा ने इस आदेश की अनुपालना के लिए प्रमोटर को वेब पोर्टल पर आदेश अपलोड होने की तिथि से 45 दिनों का समय दिया है, और इसके बाद 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट अथॉरिटी के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। रेरा का यह आदेश उन प्रमोटरों के लिए एक कड़ा सबक है जो एग्रीमेंट न होने के बावजूद खरीदारों की विवशता का फायदा उठाकर उनकी मेहनत की कमाई को अनुचित तरीके से जब्त कर लेते हैं।

लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता

(लेखक- संजय गोस्वामी)

(हिन्दी पत्रकारिता दिवस 30 मई26 पर विशेष)

पत्रकारिता समाचारों, विचारों और घटनाओं को एकत्र करके उन्हें जनता तक पहुँचाने का माध्यम है, यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसका उद्देश्य समाज को जागरूक, निष्पक्ष और सूचित रखना है इंसानी इतिहास में, पत्रकारिता ने अपनी अहम जगह और ऊँचे आदर्शों पर पक्के भरोसे के ज़रिए हमेशा अपनी अलग पहचान बनाई है। भारत में, पत्रकारिता का इतिहास लगभग दो सौ साल पुराना है। आज, पत्रकारिता शब्द हमारे लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सुबह होते ही हमें अखबार की ज़रूरत महसूस होती है; इसके बाद, पूरे दिन हमें रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे अलग-अलग तरीकों से खबरें मिलती रहती हैं। इसके अलावा, रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया सुबह से शाम तक हमारे साथ रहते हैं। इस लगातार जुड़ाव के पीछे एक खास इच्छा है—एक जिज्ञासा—नई और ताज़ा जानकारी पाने की। लोग पिछले कुछ घंटों में या पिछली रात से हुए बदलावों या सामने आई नई घटनाओं के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। इस बात का निचोड़ यह है कि हम अपने दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और साथ काम करने वालों से अपने आस-पास हो रही घटनाओं के बारे में लगातार जानना चाहते हैं। अपने आस-पास की चीज़ों, घटनाओं और लोगों के बारे में अप-टू-डेट जानकारी पाना इंसान की एक जन्मजात आदत है; जिज्ञासा की भावना हमारे अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है। यही जिज्ञासा न्यूज़ का बुनियादी हिस्सा है—और, बड़े पैमाने पर कहें तो, खुद पत्रकारिता का भी। अगर यह जिज्ञासा खत्म हो जाए, तो न्यूज़ की ज़रूरत भी खत्म हो जाएगी। पत्रकारिता इसी अंदरूनी जिज्ञासा को पूरा करने की कोशिश के तौर पर शुरू हुआ—यह एक ऐसा मिशन है जिसे यह आज भी पूरा कर रहा है, और अपने बुनियादी उसूलों पर मज़बूती से टिका हुआ है। इस जिज्ञासा के ज़रिए, हमें अपने आस-पड़ोस, शहर, राज्य और पूरी दुनिया के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। यह जानकारी न सिर्फ़ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर बल्कि पूरे समाज पर असर डालती है। इसके अलावा, यह जानकारी हमारे अगले कदम को तय करने में हमारी मदद करने में भी अहम भूमिका निभाती है। यही वजह है कि आज के समाज में इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन मीडिया का महत्व तेज़ी से बढ़ा है। आज, हम देश और दुनिया भर में हो रही घटनाओं के बारे में ज़्यादातर जानकारी अलग-अलग न्यूज़ मीडिया आउटलेट से लेते हैं। इन अलग-अलग चैनलों के ज़रिए—चाहे वह अखबार हों, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, या सोशल मीडिया—दुनिया भर की खबरें सीधे हमारे घरों तक पहुँचती हैं। न्यूज़ ऑर्गनाइज़ेशन में काम करने वाले जर्नलिस्ट लोकल और ग्लोबल लेवल पर होने वाली घटनाओं को न्यूज़ रिपोर्ट में बदलते हैं और हम तक पहुँचाते हैं। ऐसा करने के लिए, वे रोज़ाना जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसे न्यूज़ फ़ॉर्मेट में ढालते हैं और लोगों के सामने पेश करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को पत्रकारिता कहते हैं। कोई भी जानकारी जो किसी व्यक्ति, समाज, देश या पूरी दुनिया पर असर डालती है, वह न्यूज़ होती है। दूसरे शब्दों में, किसी खास घटना पर रिपोर्ट, डेफिनिशन के हिसाब से, न्यूज़ है। या, जैसा कि अक्सर कहा जाता है, न्यूज़ जल्दबाज़ी में लिखा गया इतिहास है। हिंदी शब्द "पत्रकारिता" इंग्लिश शब्द पत्रकारिता का सीधा ट्रांसलेशन है। मतलब के नज़रिए से, पत्रकारिता शब्द जर्नल से बना है, जिसका मतलब है रोज़ का रिकॉर्ड, डायरी, या डेबुक—असल में, रोज़ाना की एक्टिविटीज़ का डिटेल्ड अकाउंट वाला डॉक्यूमेंट। सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के अलावा, ये मीडिया हमें बहुत सारी जानकारी से जान-पहचान कराते हैं। इसके अलावा, एडवरटाइज़िंग ने हमें कंज्यूमर कल्चर में अच्छे से जोड़ दिया है। कुल मिलाकर, पत्रकारिता के अलग-अलग मीडियम—जैसे अखबार, मैगज़ीन, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और सोशल मीडिया—ने लोगों से लेकर ग्रुप तक और देशों से लेकर पूरी दुनिया तक, सबको एक साथ जोड़ दिया है। इसलिए, आज पत्रकारिता में नेशनल लेवल पर आइडिया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और यहाँ तक कि कल्चर को भी प्रभावित करने की काबिलियत है। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय निकालें। एक ही मोहल्ले में रहने वाले दो लोग रोज़ एक-दूसरे से मिल सकते हैं—शायद बाज़ार में, सड़क पर चलते हुए, या एक-दूसरे के घर पर। जब वे बातचीत करते हैं, तो आमतौर पर उनका पहला सवाल क्या होता है? उनका पहला सवाल हमेशा यही होता है- हालात कैसे हैं? या आप कैसे हैं? या क्या खबर है? हालाँकि ऐसे आम, रोज़मर्रा के सवालों में कुछ खास खास नहीं लग सकता है, लेकिन एक पल सोचने पर एक गहरा मतलब पता चलता है- आज, जर्नल शब्द मैगज़ीन, अखबार और डेली डेलीज़ के लिए एक निशानी के तौर पर इस्तेमाल होने लगा है। 'पत्रकारिता'—यानी, "पत्रकारिता"—अखबारों और मैगज़ीन से जुड़े एक प्रोफ़ेशन को दिखाता है, जिसमें न्यूज़ इकट्ठा करना, लिखना, एडिट करना, दिखाना और बांटना शामिल है। आज के ज़माने में, पत्रकारिता कई मीडियम जैसे अखबार, मैगज़ीन, रेडियो, टेलीविज़न, वेब पत्रकारिता, सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए विकसित हुई है। हिंदी में पत्रकारिता का मतलब असल में यही है। इस कॉन्सेप्ट को "पत्र" (लेटर/पेपर) से "पत्रकार" (पत्रकार), और आखिर में "पत्रकारिता" (पत्रकारिता) तक के विकास को देखकर समझा जा सकता है। "बृहत् हिंदी शब्दकोष" (कॉम्प्रिहेंसिव हिंदी) के अनुसार (हिंदी शब्दकोश), "पत्र" का अर्थ है कोई चिट्ठी या कागज़ का पन्ना—विशेष रूप से, ऐसा कागज़ जिस पर कुछ लिखा या छापा गया हो; कोई कागज़ या धातु की प्लेट जिस पर किसी लेन-देन से जुड़ा कोई प्रामाणिक लेख (जैसे कि दान-पत्र या ताम्र-पत्र अनुदान) अंकित हो; कोई दस्तावेज़ी रिकॉर्ड जो किसी लेन-देन या घटना के प्रमाण के रूप में काम करे (जैसे कि पट्टा या कानूनी विलेख); या, अंत में, कोई वाहन, सवारी, या समाचार-पत्र। "'पत्रकार'" का तात्पर्य किसी समाचार-पत्र के संपादक या लेखक से है। और "'पत्रकारिता'" का अर्थ है किसी पत्रकार का काम या पेशा—वह विषय-क्षेत्र जो समाचारों के विश्लेषण, संपादन और संकलन से संबंधित है। "'बृहत् शब्दकोश'" यह स्पष्ट करता है कि "'पत्र'" का तात्पर्य किसी भी ऐसे कागज़ या माध्यम से है—चाहे वह लिखित हो या मुद्रित—जो प्रामाणिक हो और किसी विशिष्ट घटना के संबंध में दस्तावेज़ी प्रमाण के रूप में कार्य करता हो। "'पत्रकार'" उस व्यक्ति को कहते हैं जो ऐसे कागज़ या दस्तावेज़ को लिखता या संपादित करता है। और "'पत्रकारिता'" उस अकादमिक विषय-क्षेत्र को कहते हैं जो इस क्षेत्र के अध्ययन और विश्लेषण के लिए समर्पित है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि, इन सभी पारंपरिक माध्यमों में, संदेशों या सूचनाओं का प्रसार ऐतिहासिक रूप से एक-तरफ़ा प्रक्रिया रही है। इस सूचना को प्राप्त करने वालों से मिलने वाली प्रतिक्रिया (फीडबैक) लगभग न के बराबर रही है। दूसरे शब्दों में, इन विभिन्न माध्यमों में, संचारक या प्रसारक आम तौर पर सूचना प्राप्त करने वालों के साथ दो-तरफ़ा संवाद स्थापित करने में असमर्थ रहे हैं। संवाद का स्तर—पत्रों और इसी तरह के अन्य माध्यमों से प्राप्तकर्ताओं से मिलने वाली प्रतिक्रिया या जवाबों के रूप में—नगण्य रहा है। हालाँकि, हाल के वर्षों में, अत्याधुनिक जनसंचार तकनीकों के आगमन के साथ, दो-तरफा संवाद बनाए रखने की प्रथा ने जड़ पकड़ना शुरू कर दिया है। किसी भी विशिष्ट घटना के संबंध में... रिपोर्टिंग ही समाचार का रूप लेती है—ऐसी सूचना जो व्यक्तियों, समाज और समग्र रूप से दुनिया को प्रभावित करती है। चूंकि यह एक ऐसी कलात्मक सेवा है जिसके माध्यम से पत्रकार शब्दों और चित्रों का उपयोग करके समकालीन घटनाओं का दैनिक वृत्तांत तैयार करते हैं, इसलिए इसे, एक अर्थ में, 'दैनिक इतिहास-लेखन' के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ऊपरी तौर पर, यह कार्य काफी सरल प्रतीत होता है वास्तविकता में, यह बिल्कुल भी आ अपनी पूर्ण स्वायत्तता के बावजूद, सामाजिक और नैतिक मूल्यों से अविभ जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए, सांप्रदा रिपोर्टिंग करते समय, एक पत्रकार करने का प्रयास करता है कि उसकी को भड़काए नहीं या आगे की हिंसा नहीं। वे दंगों के दौरान मारे गए या घा की सामुदायिक पहचान ज़ाहिर कर करते हैं।

बलात्कार से जुड़े मामलों में, पत्र का नाम या तस्वीर प्रकाशित नहीं क उसकी सामाजिक गरिमा और प्रतिष्ठ संभावित नुकसान से सुरक्षित रहती है यह अपेक्षा की जाती है कि वे पेशेवर का पालन करें, ताकि यह सुनिश्चित उनकी रिपोर्टें—अनावश्यक रूप से या के बिना—किसी की भी व्यक्तिगत नुकसान न पहुँचाएँ, और न ही अराजकता या अशांति के बीज बं पत्रकारिता इसी बात में निहित है कि व चिंताओं को सत्ता के गलियारों तक ज़िम्मेदारी निभाए, और साथ ही प्रशास कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं क सबसे निचले तबके तक प्रसारित करे को अक्सर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क लोकतांत्रिक ढाँचे के भीतर यह महत्वप अपने-आप नहीं मिल गया; बल्कि, उसे यह विशिष्ट सम्मान प्रदान किया, पत्रकारिता की सामाजिक ज़िम्मेदारि उसकी प्रतिबद्धता के गहरे महत्व क लोकतंत्र तभी वास्तव में मज़बूत हो स पत्रकारिता इन सामाजिक दायित्वों अपनी सार्थक भूमिका को प्रभावी ढंग वास्तव में, पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के करना होना चाहिए।

संपादकीय

जरूरी सत्ता परिवर्तन

कभी भाजपा के गढ़ रहे कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता वापसी में डी.के. शिवकुमार की बड़ी भूमिका मानी जाती रही है। जिस ऊर्जा व तेवरों से, उन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस संगठन व कार्यकर्ताओं को एकजुट करके लड़ाया, उससे उम्मीद थी सरकार बनने के बाद उनकी ही ताजपोशी होगी। वे न केवल संगठन के सूत्रधार ही थे, बल्कि उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों का त्रास भी झेला था। बहरहाल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से सिद्धारमैया के इस्तीफे ने अब तक उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभाते रहे डी.के. शिवकुमार की पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है। देर से ही सही कांग्रेस हाईकमान ने उस चूक को दुरुस्त किया है, जिसके चलते कई राज्यों में नेतृत्व चयन की गफलत की बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी थी। बहरहाल, 77 वर्षीय सिद्धारमैया की सरकार ने पिछले ही सप्ताह अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे किए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा है। हालांकि, राज्यभर में उनके समर्थकों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन संकेत देते हैं कि इस नेतृत्व परिवर्तन को एक सामान्य बदलाव के रूप में नहीं देखा जा सकता। कयास लगाए जा रहे हैं कि मौजूदा बदलाव मई 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद सत्ता साझाकरण की बारी-बारी से व्यवस्था की अटकलों को बल देता प्रतीत होता है। हालांकि, कांग्रेस पार्टी इस बात से इनकार करती है लेकिन ऐसा लगता है कि सत्ता के बंटवारे के इस समझौते ने कर्नाटक में पार्टी की आंतरिक गतिविधियों को प्रभावित किया है। इस बदलाव के लिये लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे डी.के. शिवकुमार अब इस प्रतिष्ठित पद के लिये और इंतजार करते नहीं दिखायी दे रहे थे। जाहिरा तौर पर पहले की तरह वर्ष 2028 के चुनावी संग्राम के लिये पार्टी को तैयार करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। उन्हें अगले दो वर्षों में राज्य में सुशासन को प्राथमिकता देनी होगी। इस बात को कुछ देर से ही सही, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने महसूस तो किया है। राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व को देर-सवेर अहसास होने लगा था कि जिस कर्नाटक को भाजपा दक्षिण का द्वार बताकर विगत में वर्चस्व बना चुकी है, वहां पार्टी को नेतृत्व-द्वंद्व का नुकसान हो सकता था। जिसकी पूर्ति तेज-तर्रार डी.के. शिवकुमार जैसे नेतृत्व से ही संभव हो सकती है। निर्विवाद रूप से वे अपेक्षाकृत कम उम्र के जुझारू राजनेता के रूप में पहचान रखते हैं। उन्हें कुशल चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाना जाता रहा है। बहरहाल, अब कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य में पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और दलितों का समर्थन बरकरार रखना है। माना जाता है कि इन वर्गों में सिद्धारमैया की खासी मजबूत पकड़ रही है। वहीं दूसरी ओर निवर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र की राजनीति में भूमिका को स्वीकार करने के लिये दिए गए प्रस्ताव पर अनिच्छा जताने ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। बहरहाल, इसी तरह के अनिर्णय व असमंजस की स्थिति का नुकसान विगत में कांग्रेस कई राज्यों में उठा चुकी है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 2018-23 तक पद पर बनाये रखा, जबकि उनके सहयोगी और प्रतिद्वंद्वी टीएस सिंह देव लगातार उन पर दबाव डाल रहे थे। पंजाब में, पार्टी ने साल 2022 के विधानसभा चुनावों से ठीक पांच महीने पहले कैप्टन अमरिंदर को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। सत्ता विरोधी लहर का मुकाबला करने के उद्देश्य से उठाया गया यह कठोर कदम कांग्रेस को बड़ा झटका दे गया था।

सवालों से बचती सत्ता और घुटनों पर बैठा मीडिया

(लेखक -दिलीप कुमार पाठक)

(30 मई हिन्दी पत्रकारिता दिवस)

30 मई को भारत में हर साल हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमारे देश में हिंदी भाषा में पहला अखबार शुरू होने की याद में मनाया जाता है। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने साल 1826 में इसे कोलकाता से शुरू किया था। उस दौर में पत्रकारिता का एक ही मकसद था, देश को आजाद कराना और समाज को जगाना। लेकिन आज जब हम इस दिन को मनाते हैं, तो खुशी से ज्यादा हमारे मन में एक चिंता होती है। आज की पत्रकारिता उस ऊंचे रास्ते से बहुत दूर आ चुकी है। आज हमारा मीडिया और पत्रकारिता का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। पत्रकारिता को कभी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था, जिसका काम जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना और सरकार की कमियों को सामने लाना था। लेकिन आज ऐसा लगता है कि यह स्तंभ कमजोर हो चुका है। अखबारों और टीवी चैनलों पर अब जनता के असली मुद्दे, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य गायब हो चुके हैं। इसकी जगह दिन-रात धर्म के नाम पर विवाद, राजनीतिक दलों की आपसी लड़ाई और गैर-जरूरी सनसनीखेज खबरें दिखाई जाती हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचने की इस अंधी दौड़ ने खबरों को सिर्फ एक तमाशा बना दिया है। भारतीय पत्रकारिता की यह गिरती हुई साख अब सिर्फ देश के भीतर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में धूमिल हो रही है। दुनिया भर में प्रेस की आजादी को नापने वाली सूची में भारत लगातार नीचे गिरकर 157वें स्थान पर पहुंच गया है। यह इस बात का साफ सबूत है कि हमारे देश में निष्पक्ष पत्रकारों के लिए काम करना कितना मुश्किल हो गया है। सरकार की कमियों पर सवाल उठाने वाले पत्रकारों को डराया-धमकाया जाता है, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं या उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है।

हाल ही में नॉर्वे दौरे पर हुई एक घटना ने वैश्विक स्तर पर भारतीय मीडिया की इस स्थिति को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। ओस्लो में एक साझा प्रेस वार्ता के बाद, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोडियम से हटने लगे, तो नॉर्वे की एक महिला पत्रकार हेला लेंग ने उनसे एक सीधा और सरल सवाल पूछा कि, पीएम मोदी आप दुनिया की सबसे आजाद प्रेस के पत्रकारों के सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? प्रधानमंत्री इस सवाल का बिना कोई जवाब दिए वहां से आगे बढ़ गए, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में फैल गया और इसने वैश्विक मंच पर भारतीय लोकतंत्र की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा।

यह घटना एक और बड़े कड़वे सच को सामने लाती है। पिछले 12 सालों के अपने कार्यकाल में पीएम मोदी ने भारत में एक भी पारंपरिक और स्वतंत्र प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जब देश का मुखिया ही खुलकर पत्रकारों के तीखे और सीधे सवालों का सामना करने से बचता है, तो नीचे की पूरी व्यवस्था में जवाबदेही खत्म होने लगती है। जब सत्ता मीडिया के सामने जवाबदेह नहीं होगी, तो मीडिया भी धीरे-धीरे जनता के मुद्दे छोड़ सिर्फ सत्ता की तारीफ करने का जरिया बन जाता है।आज सोशल मीडिया और इंटरनेट के आने से आम लोगों को अपनी बात रखने का मौका तो मिला है, लेकिन वहां भी झूठी खबरें और नफरत का बाजार गर्म है। चंद रुपयों के लिए इंटरनेट पर झूठ फैलाया जाता है, जिससे समाज में आपसी भाईचारा खत्म होता है। असली और गंभीर पत्रकारिता इस शोर में कहीं दबकर रह गई है। पत्रकारिता का जो काम समाज को जोड़ने का था, वह आज समाज को बांटने का जरिया बनता जा रहा है। इस गिरते दौर में हिंदी पत्रकारिता दिवस सिर्फ एक त्योहार की तरह मनाकर भूल जाने का दिन नहीं है। यह दिन गहराई से सोचने का है। आज मीडिया मालिकों, संपादकों और खुद पत्रकारों को यह सोचना होगा कि वे

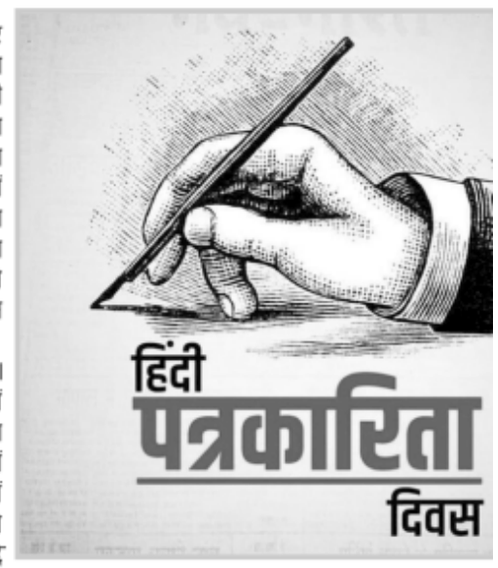

समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्या वे सिर्फ सरकारों की हां में हां मिलाना चाहते हैं या फिर आवाज बनना चाहते हैं? एक नागरिक के तौर पर जिम्मेदारी है कि हम अंधभक्ति और नफरत परोसने वा देखना बंद करें। हमें उन गिने-चुने स्वतंत्र पत्रकारों चाहिए जो खुद को जोखिम में डालकर आज भी सच जब तक जनता सच का साथ नहीं देगी, तब तक पत्रक गिरता हुआ दौर नहीं सुधरेगा। आइए, इस हिंदी पत्रक पर हम सच के साथ खड़े होने का संकल्प लें, ताकि यह चौथा खंभा फिर से मजबूत हो सके।

(लेखक पत्रकार हैं)

सदाचार की परीक्षा

राजा अंग सिंह के पुत्र प्रवीण सिंह गलत संगति में पड़कर अनुचित कार्य करने लगा। चारों तरफ से उसकी शिकायतें आने लगीं। इससे राजा अत्यंत चिंतित हो गए। प्रवीण सिंह अभी बालक ही था, इसलिए राजा चाहते थे कि उसका स्वभाव बदले और भविष्य में वह एक नेक राजा बन सके।

वह उसे अपने गुरु सोमदेव के पास लेकर आए। सोमदेव ने युवराज को छह माह तक अपने आश्रम में छोड़ देने के लिए कहा। वह प्रतिदिन युवराज को अपने साथ रखते और उससे कई कार्य कराते। इसी तरह तीन महीने बीत गए। अब राजकुमार पर सुसंगति के साथ ही गुरुदेव की बातों का असर पड़ने लगा था। एक दिन गुरु बोले, पुत्र, ईश्वर हर जगह मौजूद है। याद रखो दुष्कर्म और पाप की सजा मिलती अवश्य है क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहा होता है। जब तुम किसी प्रलोभन से पाप करने को उतारू हो तो वहीं ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करो। तुम हर जगह यह सोचो कि मेरा प्रभु मेरे सामने है।

वह ये बातें प्रतिदिन युवराज को बताते। एक दिन उन्होंने रा एक खरगोश देकर उसे एकांत में ले जाकर मारने को क खरगोश को लेकर कई स्थानों पर गया लेकिन उसकी गर्दन पाया। वह जब भी उसकी गर्दन पर हाथ रखता तो उसकी निर्द उसे ईश्वर नजर आते। कई घंटों बाद वह वापस जीवित खरगो गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरु जी आप ही ने तो सिखाय किसी में ईश्वर की उपस्थिति समझो। फिर मैं अकेला कैसे हो इस खरगोश की भोली आंखों में मुझे ईश्वर की उपस्थिति इसलिए मैं इसे मार नहीं पाया। युवराज की बात सुनकर गुर उसे गले से लगा लिया और बोले, पुत्र, आज तुम सदाचार परीक्षा में पास हो गए हो। इसके बाद महाराज उसे अपने साथ ले

विचार मंथन

शेयर बाजार में भारतीय निवेशकों के 13 लाख करोड़ डूबे

लेखक- सनत जैन

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो ताजा रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। उसके अनुसार भारतीय शेयर बाजार में पिछले तीन माह में भारी उतार चढ़ाव के कारण निवेशकों के 13 लाख करोड रुपए शेयर बाजार में डूब गए हैं। चौथी तिमाही में निफ्टी 50 में 10 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। भारतीय शेयर बाजार में जिस तरह की गिरावट निरंतर बनी हुई है। उसने भारत के संस्थागत निवेशक वित्तीय संस्थान बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम की चिंताऐं तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरह से तनाव बना हुआ है। यह आगे और बढ़ता हुआ दिख रहा है। दुनिया के अधिकांश देशों में ऊर्जा संकट लगातार बढ़ रहा है। ऊर्जा संकट के कारण अर्थव्यवस्था में भारी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। ऊर्जा संकट ने पूरी दुनिया में एक अलग तरह के आर्थिक संकट को जन्म दिया है। कच्चे तेल और गैस इत्यादि के बढ़ते दाम, उपलब्धता में लगातार कमी से शेयर बाजारों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। विदेशी निवेशक भारत से अपना निवेश निकलकर भाग रहे हैं। 2026 एनएसई की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है।उसके अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों में घरेलू निवेशकों की कुल हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। विदेशी निवेशक लगातार कई वर्षों से मुनाफा वसूली कर रहे थे। भारत का पैसा मुनाफे के रूप में विदेशों में चला गया है। विदेशी निवेश लगातार निकलने के कारण वहीं विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी न्यूनतम स्तर पर आ गई है। लगातार गिरावट के कारण भारत में घरेलू निवेशकों का फंड घटकर 76. 5 लाख करोड रुपए रह गया है. पिछली तिमाही के आधार पर लगभग 13 फीसदी की गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो में निवेशकों ने 19.6 अरब डॉलर भारतीय शेयर बाजार से निकाल लिए हैं। सूचीबद्ध कंपनियों में विदेशी निवेशको की हिस्सेदारी घटकर 17 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। जो वर्तमान में चिंता का सबसे बड़ा कारण बन गया है। शेयर बाजार के साथ-साथ विदेशी मुद्रा का संकट भी भारत में बढ़ता चला जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार गिर रही है। कच्चे तेल और गैस की कीमतें बढ़ने और डॉलर मुद्रा में भुगतान के कारण आर्थिक स्थिति में बड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। चीन से आयात की तुलना में निर्यात बहुत कम है।युवान मुद्रा को लेकर भी लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में फंसती चली जा रही है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है, डॉलर से ज्यादा खराब स्थिति युवान के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को झेलना पड़ रही है। चीन से भारत का आयात निर्यात में अंतर बढ़ता चला जा रहा है। राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था दो पाटों के बीच में फंसकर रह गई है। डॉलर और युवान दोनों ही भारत के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। जिस तरह की स्थिति वर्तमान में बन रही है। उसने सभी अर्थशास्त्रियों को चिंता में डाल दिया है। डीजल और पेट्रोल की कीमतें चार बार बढ़ा दी गई हैं। इसका असर महंगाई पर पड़ रहा है। महंगा डीजल पेट्रोल महंगाई को बढ़ाने का काम कर रहा है। सरकार ने औद्योगिक कंपनियों के लिए डीजल का रेट बढ़ाकर 149 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 54 रुपए प्रति लीटर ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है।

इसका असर सभी उत्पाद पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था का संकट सभी के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। शेयर बाजार और भारतीय अर्थव्यवस्था में जिस तरह की नकारात्मकता देखने को मिल रही है। उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है। सरकार ने वास्तविकता को स्वी हुए यदि कठोर निर्णय नहीं लिए तो स्थिति बद हो सकती है। केंद्र सरकार और रिजर्व स्थितियों का मुकाबला करने के लिए जिस प्रयास करने चाहिए, उस तरह के प्रयास कहीं हुए नही दिख रहे हैं। उल्टा सरकार वर्तमान मुकाबला आंख मूंदकर, भगवान भरोसे संकट मुंह मोड़ रही है। उसके कारण स्थिति दिनों हो रही है। सरकार अभी भी यह मानकर च कुछ दिनों के बाद स्थिति ठीक हो जाएगी। हो होने के स्थान पर दिन प्रतिदिन खराब होत है।सरकार को गंभीरता से वर्तमान स्थिति करना चाहिए। आम जनता और विपक्ष को स्थिति से अवगत कराते हुए, संकट का सा तरह से करना है। इसके लिए सभी को विश्वा जरूरी है।

वैश्विक उथल-पुथल से किचन का बजट बिगड़ा, खाद्य तेल 13 फीसदी महंगा

एफएमसीजी कंपनियों पर भी बढ़ा बोझ, पैकेज्ड फूड भी होगा महंगा

नई दिल्ली ।

पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मची उथल-पुथल का सीधा असर अब भारतीय घरों की रसोई पर दिख रहा है। फरवरी से अब तक खाद्य तेलों की थोक कीमतों में करीब 13 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे आम परिवारों का मासिक बजट बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती महंगाई के बाद खाद्य तेलों की यह नई मार उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी चिंता बन गई है। विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिम एशिया में तनाव से परिवहन, बीमा और शिपिंग लागत में भारी वृद्धि हुई है। डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी से पाम तेल का आयात भी महंगा हुआ है। इसके अलावा, इंडोनेशिया के बायोफ्यूल में 50 फीसदी पाम तेल मिश्रण कार्यक्रम से वैश्विक आपूर्ति और घट सकती है, जिससे कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है। भारत अपनी लगभग 60 फीसदी खाद्य तेल जरूरतें आयात करता है, इसलिए वैश्विक संकटों का असर यहां तेजी से महसूस होता है। बढ़ती ईंधन कीमतें किसानों की लागत और माल ढुलाई खर्च भी बढ़ा रही हैं। इसका असर अब एफएमसीजी सेक्टर पर भी दिख रहा है। नमकीन, बिस्कुट और बेकरी आइटम बनाने वाली कंपनियों की इनपुट लागत बढ़ गई है। उद्योग विशेषज्ञ मानते हैं कि कंपनियां जल्द ही यह बोझ उपभोक्ताओं पर डालेंगी, जिससे पैकेज्ड फूड भी महंगा हो जाएगा।

वैश्विक बाधाओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत- आरबीआई

मजबूत वृहद आर्थिक आधार, पूंजीगत व्यय और बेहतर बैंकिंग बही-खाते वृद्धि को देंगे सहारा

नई दिल्ली।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2026-27 में मजबूत बनी रहेगी। केंद्रीय बैंक ने सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए बताया कि देश के मजबूत वृहद आर्थिक आधार, कंपनियों एवं बैंकिंग क्षेत्र के बेहतर बही-खाते और सरकार के पूंजीगत व्यय पर जोर से आगामी वित्त वर्ष में वृद्धि को बल मिलेगा। हालांकि, पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और अन्य वैश्विक चुनौतियां प्रमुख जोखिम बनी रहेंगी। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार ऊंची ऊर्जा कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं और वैश्विक बाजारों से आने वाली चुनौतियों के बावजूद भारत की वृद्धि गति मजबूत बनी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026 में उभरे भू-राजनीतिक जोखिम, विशेषकर पश्चिम एशिया में संघर्ष का लंबा खिंचना, वैश्विक वृद्धि और मुद्रास्फीति के अनुमानों के लिए एक नकारात्मक जोखिम उत्पन्न कर सकता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करेगा। इसके बावजूद रिपोर्ट में कहा गया कि मध्यम वैश्विक वृद्धि के परिदृश्य के बीच वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है। भारत वित्त वर्ष 2025-26 में 7.6 प्रतिशत की दर से बढ़ते हुए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश बना रहा, जबकि 2024-25 में यह वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत थी। यह मजबूत घरेलू मांग, निरंतर निवेश, सक्रिय नीतिगत पहल और ठोस व्यापक आर्थिक आधार से समर्थित रही। विभिन्न व्यापार समझौतों का क्रियान्वयन भी वृद्धि को गति देगा। कृषि क्षेत्र का परिदृश्य दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति पर निर्भर करेगा। अल नीनो की संभावना कृषि उत्पादन के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा करती है, हालांकि हिंद महासागर द्विध्रुवीय स्थिति इसके प्रतिकूल प्रभावों को आंशिक रूप से कम कर सकती है। मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव कच्चे माल, विशेषकर उर्वरकों की उपलब्धता और कीमतों पर दबाव डाल सकते हैं, लेकिन सरकार के विविध स्रोतों से आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयासों से इन चिंताओं को कम करने में मदद मिलेगी। आरबीआई ने कहा कि 2026-27 में मुद्रास्फीति के तय लक्ष्य (4 प्रतिशत, दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ) के अनुरूप रहने की संभावना है, भले ही अल नीनो की स्थिति और सामान्य से अधिक गर्मी हो। यह पर्याप्त खाद्यान्न भंडार और जलाशयों में जल स्तर के कारण संभव होगा। भविष्य की पहल के तौर पर आरबीआई केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) के परीक्षणात्मक उपयोग का विस्तार करने और वित्तीय परिसंपत्तियों के टोकनाइजेशन पर विचार कर रहा है।

शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद

सेंसेक्स 1,092 , निफ्टी 359 अंक गिरा

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को भारी गिरावट पर बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन बाजार में ये गिरावट दुनिया भर के बाजारों से मिले-जुले संकेतों के कारण बिकवाली हावी रहने से आई है। आज सुबह भारतीय बजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई पर अमेरिका-ईरान समझौते को लेकर संशय पनपने से बाजार नीचे आने लगा। इसी कारण दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स कारोबार के अंत में 1,092.06 अंक टूटकर 74,775.74 पर पहुंच गया जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 359.40 अंक टूटकर 23,547.75 पर आ गया। आज कारोबार के दौरान एक समय सेंसेक्स 76,220.02 तक पहुंचा। वहीं निफ्टी 24,002.80 तक उछला। व्यापक बाजारों में, निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 1.33 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.85 फीसदी की गिरावट रही।

वहीं क्षेत्रवार देखें तो, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 2.47 फीसदी की गिरावट, निफ्टी मेटल में 2.02 फीसदी की गिरावट और निफ्टी वित्तीय सेवाओं में 2.02 फीसदी की गिरावट रही। इसके अलावा, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी हेल्थकेयर और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1 फीसदी से ज्यादा की गिरावट रही। वहीं निफ्टी आईटी इंडेक्स में 0.60 फीसदी की बढ़त रही। आज एचसीएल टेक, विप्रो, नेस्ले इंडिया और एलएंडटी के शेयरों में 1 फीसदी से ज्यादा की तेजी रही।

वहीं इंडिगो, ओएनजीसी, मैक्सहेल्थ, आयशर मोटर के के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। आज बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण पिछले सत्र के लगभग 471 लाख करोड़ रुपए से गिरकर करीब 465 लाख करोड़ रुपए रह गया। इससे एक ही सत्र में निवेशकों को करीब 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

रुपया बढ़त के साथ बंद

मुंबई ।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले शुक्रवार को भारतीय रुपया शुरुआती कारोबार में 67 पैसे की बढ़त के साथ ही 94.91 पर बंद हुआ। आज सुबह भारतीय रुपया पांच पैसे मजूबत होकर 95.53 पर खुला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.77 पर खुला और शुरुआती कारोबार में बढ़त बनाते हुए 95.53 तक पहुंच गया, जो इसके पिछले बंद भाव से पांच पैसे की मजबूती दर्शाता है। डॉलर के मुकाबले शुरुआती कारोबार में रुपया 95.78 तक भी गया। रुपया बुधवार को 12 पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.58 पर बंद हुआ था। ईद-उल-अजहा के अवसर पर गुरुवार को घरेलू शेयर और विदेशी मुद्रा बाजार बंद थे। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.07 फीसदी की बढ़त के साथ 99.09 पर रहा।

नेट न्यूट्रैलिटी विवाद में कूदी वीआई, एयरटेल की 5जी प्राथमिकता पर जताई चिंता

कंपनी ने कहा, सबको समान इंटरनेट अनुभव मिलना चाहिए

नई दिल्ली ।

भारत की तीसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया (वीआई) ने हाल ही में भारती एयरटेल की कुछ 5जी-आधारित पोस्टपेड योजनाओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कंपनी का मानना है कि ये योजनाएं, जो कुछ ग्राहकों को प्राथमिकता वाली नेटवर्क सेवाएं प्रदान करती हैं, नेट न्यूट्रैलिटी के सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकती हैं और सभी उपयोगकर्ताओं के लिए समान इंटरनेट अनुभव के अधिकार को प्रभावित कर सकती हैं।

यह मुद्दा तब सामने आया है जब संसद की एक स्थायी समिति भी ऐसी सेवाओं की वैधता की जांच कर रही है। सभी के लिए समान और सुलभ इंटरनेट कनेक्टिविटी को खतरे में देखते हुए, दूरसंचार परिचालक वोडाफोन आइडिया ने भारती एयरटेल की 5जी स्लाइसिंग पर आधारित प्राथमिकता वाली पोस्टपेड योजनाओं पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। वीआई ने उपभोक्ता हितों को प्रमुखता देते हुए तर्क दिया है कि किसी उपयोगकर्ता के प्रोफाइल के आधार पर विशेष नेटवर्क गति या सेवाएं प्रदान करना नेट न्यूट्रैलिटी नियमों का उल्लंघन है और डिजिटल तंत्र की समानता पर सवाल उठाता है। कंपनी के एक वे रिष्ठ अे धिकारी ने स्पष्ट किया कि भारत की डिजिटल वृद्धि सभी के लिए किफायती और सुलभ कनेक्टिविटी पर टिकी है। उन्होंने जोर दिया कि हर उपभोक्ता को एक समान और निर्बाध नेटवर्क अनुभव मिलना चाहिए।

भारत को डिजिटल वृद्धि जारी रखने के लिए तकनीक में प्रगति के साथ-साथ, नवाचार और पैसा बनाने के मॉडल में सभी ग्राहकों के हितों को प्राथमिकता देना जरूरी है। पारदर्शिता और सब तक इसकी उपलब्धता अहम हैं।

जापान नहीं जाएगा भारतीय आम, आम निर्यातक और किसान की बढ़ी चिंता

अधिकारियों को सफाई व्यवस्था और फ्यूमिगेशन प्रक्रिया में मिलीं तकनीकी खामियां

नई दिल्ली।

भारतीय आमों की मिठास इस बार जापान तक नहीं पहुंच पाएगी। करीब दो दशक पहले हटाए गए प्रतिबंध के बाद लगातार जारी भारतीय आमों के निर्यात पर जापान ने एक बार फिर अस्थायी रोक लगा दी है। इस फैसले से आम निर्यातकों और किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि यह प्रतिबंध ऐसे समय लगाया गया है जब अप्रैल से जून के बीच आमों का निर्यात अपने चरम पर होता है। इस रोक का सबसे ज्यादा असर अल्फांसो, केसर, लंगड़ा और बंगनपल्ली जैसी आम किस्मों पर पड़ेगा, जिनकी जापान में अच्छी मांग है।

जानकारी के मुताबिक जापान हर साल आम के निर्यात सीजन से पहले अपनी क्वारंटीन टीम भारत भेजता है। यह टीम उन वेपर हीट ट्रीटमेंट केंद्रों का निरीक्षण करती है, जहां जापान भेजे जाने वाले आमों को प्रोसेस किया जाता है। इस प्रक्रिया में आमों को गर्म और नमी वाली हवा में रखा जाता है ताकि फल मक्खियों और अन्य कीटों को खत्म किया जा सके। जापान के लिए आम निर्यात करने में यह प्रक्रिया अनिवार्य है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल मार्च में उत्तर प्रदेश के रहमानपुर स्थित वेपर हीट ट्रीटमेंट केंद्र का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान जापानी अधिकारियों को वहां सफाई व्यवस्था और फ्यूमिगेशन प्रक्रिया से जुड़ी कुछ तकनीकी खामियां मिलीं। हालांकि दोनों देशों की सरकारों ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वास्तव में कौन-कौन सी कमियां मिली। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि मौजूदा निर्यात सीजन के दौरान यह समस्या सुलझ पाएगी या नहीं। जापान के प्लांट प्रोटेक्शन स्टेशन और भारत की कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अभी तक किसी समयसीमा की घोषणा नहीं की है। इस कारण निर्यातकों के सामने अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है।

बता दें जापान ने पहली बार 1986 में भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि उसे फल मक्खियों के संक्रमण का खतरा था। करीब 20 साल बाद 23 जून 2006 को यह प्रतिबंध हटाया गया था और उसके बाद भारत से जापान को आमों का निर्यात दोबारा शुरू हुआ। जापान ने केवल छह भारतीय किस्मों अल्फांसो, केसर, बंगनपल्ली, लंगड़ा, चौसा और मलिका को आयात की अनुमति दी थी। इन आमों को निर्यात से पहले वेपर हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य किया गया था। हालांकि जापान भारतीय आमों का सबसे बड़ा बाजार नहीं है, लेकिन यह प्रीमियम बाजार माना जाता है। जापान में भारतीय आमों को ऊंची कीमत मिलती है, इसलिए यह प्रतिबंध निर्यातकों की कमाई पर सीधा असर डाल सकता है।

वैश्विक अस्थिरता के बीच अर्थव्यवस्था मजबूत, चालू खाता घाटा निर्धारित स्तर के अंदर

आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जारी वार्षिक रिपोर्ट

नई दिल्ली।

वैश्विक अस्थिरता के बीच देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है।वहीं, चालू खाता घाटा निर्धारित स्तर के अंदर बना हुआ है। यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से शुक्रवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जारी वार्षिक रिपोर्ट में दी गई। आरबीआई ने रिपोर्ट में कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बने रहने के बावजूद, स्थिर घरेलू मांग और मजबूत सेवा क्षेत्र के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था 2025-26 में भी मजबूत बनी रही। खाद्य पदार्थों में अपस्फीति और मजबूत अनुकूल आधार प्रभाव के कारण मुख्य महंगाई दर में नरमी आई। वहीं, जमा और ऋण में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। केंद्र सरकार राजकोषीय समेकन जारी रखे हुए हैं और पूंजीगत व्यय पर लगातार जोर दिया है। वहीं, वैश्विक अनिश्चितता में इजाफे के बाद भी बाह्य क्षेत्र लचीला बना हुआ है। आरबीआई के मुताबिक 2025-26 में चालू खाता घाटा अपने निर्धारित स्तर के भीतर ही रहा और विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त स्तर पर बना रहा, जिससे व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को समर्थन मिला। भारतीय वित्तीय बाजारों ने लचीलापन प्रदर्शित किया, जिसमें मुद्रा बाजार दरें नीतिगत रेपो दर और मौजूदा तरलता स्थितियों के अनुरूप विकसित हुईं। केंद्रीय बैंक के मुताबिक, 2025-26 में इक्विटी बाजारों में द्विदिशात्मक गति देखी गई। एक तरफ सहायक मौद्रिक और राजकोषीय नीति उपायों ने बाजार भावना को बेहतर बनाया, जबकि भू-राजनीतिक और टैरिफ अनिश्चितताओं, और एआई से संबंधित चिंताओं से उत्पन्न नकारात्मक वैश्विक संकेतों ने दबाव बनाने का काम किया। वहीं, अप्रैल 2025 में अमेरिकी टैरिफ जैसे बाहरी झटकों के बाद भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहा। देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर निवेश, उपभोग में वृद्धि और सेवा क्षेत्र में मजबूती और आपूर्ति पक्ष में औद्योगिक गतिविधि में सुधार से गति मिल रही है।

भारत-कनाडा ने व्यापार एवं निवेश मंच का अनावरण किया

व्यापारिक सहयोग बढ़ाने और संपर्क मजबूत करने पर जोर

नई दिल्ली ।

भारत और कनाडा ने आपसी व्यापारिक सहयोग को नई गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है।

दोनों देशों ने संयुक्त रूप से एक व्यापार एवं निवेश मंच की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य व्यवसायों को एक साथ लाना और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की हालिया कनाडा यात्रा के समापन के बाद शुक्रवार को जारी एक संयुक्त बयान में यह जानकारी दी गई। इस नए मंच का मुख्य लक्ष्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और व्यावसायिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है। बयान में कहा गया है कि भारत और कनाडा ने लोगों के बीच संपर्क, व्यापारिक सुगमता और प्रत्यक्ष वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है, जिन्हें व्यापार एवं निवेश के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। मंत्री गोयल ने अपनी तीन दिवसीय (25-27 मई) कनाडा यात्रा के दौरान व्यापार जगत के कई दिग्गजों से मुलाकात की और अपने कनाडाई समकक्ष मनींदर सिद्धू के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। यह कदम दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक सिद्ध होगा।

पेट्रोल पंप पर अब ग्राहक चुन सकेंगे अपना इथेनॉल ब्लेंड्स

सरकारी व निजी तेल कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के निर्देश

नई दिल्ली । भारत सरकार ने देश के पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को एक बड़ी सुविधा देने का ऐलान किया है। अब वाहन मालिक अपनी गाड़ी के इंजन की क्षमता और अनुकूलता के हिसाब से ई20, ई22, ई25 और ई30 जैसे अलग-अलग इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल विकल्पों में से अपनी पसंद का ईंधन चुन सकेंगे। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) जैसी सरकारी तेल कंपनियों के साथ-साथ निजी रिटेलर्स जैसे जियो-बीपी, नायरा और शेल को भी आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

इसके तहत देश भर के पेट्रोल पंपों पर विभिन्न इथेनॉल ब्लेंड्स के लिए अलग-अलग नोजल और डिस्प्ले की व्यवस्था की जाएगी।कंपनियों को नई डिस्पेंसिंग यूनिट्स, स्टोरेज सिस्टम, ब्लेंडिंग कंट्रोल और ईंधन की गुणवत्ता की निगरानी करने वाले तंत्र में निवेश करना होगा। ग्राहकों की सुविधा के लिए पंपों पर इथेनॉल मिश्रणों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा और इथेनॉल की मात्रा के आधार पर कीमतें भी अलग-अलग होंगी।

पीसी ज्वैलर का शानदार कमबैक- 90 प्रतिशत से अधिक कर्ज चुकाया, शेयर बना रॉकेट

मुंबई ।

ज्वैलरी कंपनी पीसी ज्वैलर के शेयर सोमवार को 11 प्रतिशत से अधिक की तूफानी तेजी के साथ 10.48 रुपये पर पहुंचे। इस उछाल का मुख्य कारण कंपनी द्वारा 90 प्रतिशत से अधिक बकाया कर्ज का भुगतान और जल्द ही पूरी तरह से कर्ज मुक्त होने का ऐलान है।

कंपनी अब पूर्णतः कर्ज मुक्त होकर बाजार में अपनी आक्रामक विस्तार की योजना बना रही है, इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। पीसी ज्वैलर लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर बलराम गर्ग ने बताया कि बैंकों के साथ सेटलमेंट एग्रीमेंट के बाद से कंपनी ने अपने बकाया कर्ज का 90 प्रतिशत से अधिक सफलतापूर्वक चुकाया है। उन्होंने भरोसा जताया कि कंपनी बहुत जल्द कर्ज-मुक्त होगी, जिसके बाद वह अपने वित्तीय लक्ष्यों को तेजी से आगे बढ़ाएगी। मैनेजिंग डायरेक्टर गर्ग ने वित्त वर्ष 2026 को कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष बताया, जहां इसने अपनी गति वापस हासिल की और पूरे साल शानदार प्रदर्शन दर्ज किया। वित्तीय प्रदर्शन के मुताबिक 31 मार्च 2026 को समाप्त हुई तिमाही में पीसी ज्वैलर का मुनाफा सालाना आधार पर 61.3 प्रतिशत बढ़कर 152.9 करोड़ रुपये रहा, जो बीते साल की समान अवधि में 94.8 करोड़ रुपये था। कंपनी का राजस्व भी 32.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 927.3 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल यह 699 करोड़ रुपये था। इस तिमाही में कंपनी का इबिट्डा 13.4 प्रतिशत बढ़कर 164.5 करोड़ रुपये रहा, जिसमें इबिट्डा मार्जिन 17.7 प्रतिशत दर्ज किया गया।

कंपनी ने अपने शेयरधारकों को पहले भी लाभ पहुंचाया है। जुलाई 2017 में 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए गए थे, और दिसंबर 2024 में 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर को 1-1 रुपये के 10 शेयरों में विभाजित (स्टॉक स्प्लिट) किया गया था। पिछले छह सालों में पीसी ज्वैलर के शेयरों में 800 प्रतिशत से अधिक का उछाल आया है, जबकि पिछले पांच दिनों में इसमें 19 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है, जो कंपनी की मजबूत वापसी और निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है।

अशोक लीलैंड का रिकॉर्ड प्रदर्शन, मुनाफा 1,400 करोड़ के पार

वाणिज्यिक वाहन निर्माता ने 2026 की चौथी तिमाही में अब तक का सर्वाधिक मुनाफा कमाया

नई दिल्ली ।

भारतीय वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अशोक लीलैंड ने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में 1,405 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज कर शानदार प्रदर्शन किया है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि से 13 फीसदी अधिक है। कंपनी ने तिमाही और पूरे वित्त वर्ष दोनों के लिए रिकॉर्ड राजस्व, एबिटा और वाहन बिक्री के साथ अपनी अब तक की सबसे बेहतरीन वित्तीय स्थिति पेश की है। अशोक लीलैंड का परिचालन राजस्व समीक्षाधीन तिमाही में 19 फीसदी बढ़कर 14,160.49 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एबिटा 15 फीसदी की वृद्धि के साथ 2,066 करोड़ रुपये रहा। कंपनी के एक वे रिष्ठ अे धिकारी ने बताया कि सरकार के जीएसटी 2.0 प्रोत्साहन और वाहनों की प्रतिस्थापन मांग ने इस जोरदार प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाई। कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 के लिए 800-1,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की योजना भी पेश की है। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, अशोक लीलैंड का शुद्ध लाभ 8 फीसदी बढ़कर 3,566 करोड़ रुपये रहा, जो नई श्रम संहिता के कारण 308 करोड़ रुपये के एकमुश्त बोझ के बावजूद हासिल हुआ। इस दौरान कुल राजस्व रिकॉर्ड 44,007 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, और एबिटा 13 फीसदी बढ़कर 5,732 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने 5,899 करोड़ रुपये की शुद्ध नकदी के साथ वर्ष का समापन किया। वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री भी 13 फीसदी बढ़कर 2,20,437 इकाइयों के नए सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गई, जो वित्त वर्ष 2019 के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ती है। निदेशक मंडल ने 1 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर 2.50 रुपये के दूसरे अंतरिम लाभांश की घोषणा की है। इस बीच हवाई अड्डा संचालक जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड (जीएएल) ने भी शानदार वित्तीय परिणाम पेश किए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में कंपनी घाटे से उबरकर 400.49 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ में आ गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में उसे 252.66 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था।

दिल्ली, हैदराबाद सहित कई शहरों में हवाई अड्डों का संचालन करने वाली जीएमआर एयरपोर्ट्स ने पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में 472 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया, जबकि इसकी कुल आय बढ़कर 15,200.75 करोड़ रुपये हो गई।

एलआईसी शेयरों में गिरावट नहीं, दोगुनी हुई निवेशकों की हिस्सेदारी

ऐतिहासिक 1-1 बोनस शेयर के साथ 10 प्रति शेयर डिविडेंड घोषित

मुंबई ।

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के शेयरों में शुक्रवार को आई लगभग 50 फीसदी की गिरावट ने निवेशकों को भले ही चौंकाया हो, लेकिन यह चिंता का विषय नहीं है। दरअसल, कंपनी ने अपने इतिहास में पहली बार 1-1 बोनस शेयर जारी किए हैं, जिसके चलते यह प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिला। शेयर 823 रुपए के स्तर से टूटकर 416 रुपए पर आ गया, जो रिकॉर्ड डेट पर बोनस शेयरों के लिए किया गया सामान्य समायोजन है। इसका अर्थ है कि निवेशकों के पास मौजूद हर एक शेयर के बदले उन्हें एक अतिरिक्त शेयर मुफ्त में मिला है, जिससे उनकी कुल शेयरहोल्डिंग दोगुनी हो गई है। यह ऐतिहासिक फैसला कंपनी के मजबूत वित्तीय नतीजों के बाद लिया गया, जहां मार्च तिमाही में शुद्ध लाभ 23 फीसदी बढ़कर 23,420 करोड़ रुपए रहा। बोनस के साथ एलआईसी ने शेयरधारकों के लिए 10 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की भी घोषणा की है। जानकारों का मानना है कि शेयरों की संख्या बढ़ने से बाजार में इसकी लिक्विडिटी बढ़ेगी, जिससे छोटे निवेशकों के लिए इसमें निवेश करना और भी सुलभ हो जाएगा। एडजस्टमेंट के बाद, शेयर मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है, और कंपनी का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2.65 लाख करोड़ रुपए है।

छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं: पीएम मोदी खुद कर रहे मामले की निगरानी

सुप्रीम कोर्ट ने : राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को लगा दी कड़ी फटकार

नई दिल्ली ।

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट (नीट) में सामने आई गंभीर अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को कड़ी फटकार लगा दी है। शीर्ष अदालत ने दो टूक कहा कि यह बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है और लाखों छात्रों व उनके परिवारों के लिए पूरा मामला बेहद दर्दनाक और परेशान करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त कर कहा कि छात्र अपनी युवावस्था के सबसे महत्वपूर्ण साल, अपना समय, पैसा और भावनाएं परीक्षा में लगाते हैं। इसके बाद में, यदि हर साल परीक्षा की विश्वसनीयता और शुचिता पर सवाल उठते हैं, तब यह पूरे शिक्षा तंत्र पर एक बड़ा दाग है। इस बीच, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे विवाद पर निगरानी रख रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होगी। इस गंभीर स्थिति के बीच, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (फाइमा) और यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (यूडीएफ) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एनटीए को भंग करने या उसके पूरे ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन की मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने भविष्य में मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र और विश्वसनीय संस्था के गठन की वकालत की, ताकि छात्रों का खोया हुआ विश्वास बहाल हो सके।

मामले की सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने एनटीए और पूर्व इसरो प्रमुख डॉ. के. राधाकृष्णन से सीधे सवाल पूछा कि आखिर बार-बार पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं। शीर्ष अदालत ने एनटीए के पिछले दावों पर सवाल उठाकर कहा, आपने कहा था कि मजबूत और सुरक्षित व्यवस्था बनेगी। फिर हर बार ऐसी घटनाएं कैसे हो रही हैं? कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि या समिति की सिफारिशें नाकाम साबित हुई हैं या फिर उन्हें सही तरीके से लागू नहीं किया गया।

एनटीए प्रमुख डॉ. राधाकृष्णन, जो सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद थे, ने बताया कि 2024 में बनी समिति ने करीब 35 लंबी अवधि और 60 छोटी अवधि की सिफारिशें दी थीं, जिनमें से ज्यादातर लागू भी कर दी गई हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट इस जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा और जवाबदेही तय करने पर जोर दिया। अदालत ने कहा, जिम्मेदारी किसी के कंधे पर तय होनी चाहिए। हमें बताइए कि आखिर इन गड़बड़ियों के लिए

जवाबदेह व्यक्ति कौन है? यह टिप्पणी इस बात पर जोर देती है कि सिर्फ प्रणालीगत खामियों की बात करने की बजाय, व्यक्तिगत जवाबदेही तय करना जरुरी है। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा कि केवल सिफारिशें बना देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी निगरानी और क्रियान्वयन की प्रक्रिया कितनी मजबूत थी, यह असली सवाल है। उन्होंने कहा कि यदि एक उच्च स्तरीय समिति बनने के बाद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तब या सिफारिशों में कमी है या उन्हें जमीन पर ठीक से लागू नहीं किया गया।

नाबालिग से गैंगरेप का आरोपी दरोगा अरेस्ट

कानपुर ।

कानपुर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में फरार चल रहे आरोपी दरोगा अमित कुमार मौर्या को पुलिस 144 दिन बाद गिरफ्तार कर सकी। आरोपी दरोगा पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। आरोप है कि 5 जनवरी को दरोगा ने यूट्यूबर शिवबरन सिंह के साथ मिलकर सचेंडी क्षेत्र निवासी 14 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया। इसके बाद पुलिस ने यूट्यूबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि आरोपी दरोगा फरार चल रहा था। पीड़ित लड़की के मुताबिक, 5 जनवरी की रात करीब 9.30 बजे वह शौच के लिए घर से बाहर गई थी। इसी दौरान भीमसेन चौकी में तैनात दरोगा अमित कुमार मौर्या और यूट्यूबर शिवबरन यादव ने उसके साथ गैंगरेप किया। करीब 45 मिनट तक उसके साथ दरिंदगी हुई। मामले में किशोरी की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

पूर्व सपा नेता नवाब सिंह को 8 साल की सजा

कन्नौज।

नाबालिग से रेप के आरोपी और पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव और उसके भाई नीलू को गैंगस्टर मामले में 8-8 साल की सजा हुई है। कन्नौज कोर्ट ने शुक्रवार को इसी मामले में सहआरोपी पूजा तोमर को भी 6 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने नवाब और नीलू पर 10-10 लाख रुपए और पूजा तोमर पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। नवाब सिंह यादव को दो साल पहले 15 साल की नाबालिग से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पीड़ित को पूजा तोमर नवाब सिंह के पास लेकर पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे सह-आरोपी बनाया था। जांच में सामने आया कि नवाब सिंह के भाई नीलू ने साक्ष्य मिटाने और जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने नीलू और नाबालिग की रिश्तेदार को भी गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी।

फैसलों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्तः हाईकोर्ट को 3 महीने की समय-सीमा

नई दिल्ली ।

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाईकोर्ट और निचली अदालतों में फैसलों में होने वाली देरी पर कड़ा रुख दिखाया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने न्यायपालिका की मूल जिम्मेदारी बताकर लंबित मामलों को अनिश्चितकाल तक रोकने को अस्वीकार्य किया है। सुप्रीम कोर्ट ने समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण और बाध्यकारी निर्देश जारी किए हैं। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग कर शीर्ष अदालत ने सभी हाईकोर्ट को लंबित मामलों में अधिकतम 3 महीने के अंदर निर्णय सुनाने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि फैसले के मुख्य हिस्से को सुनाने की तिथि ही निर्णय की आधिकारिक तिथि मानी जाएगी। शीर्ष अदालत ने जोर दिया कि हाईकोर्ट देश की प्राथमिक न्यायिक संस्थाएं हैं, जहां लाखों लोग न्याय की उम्मीद से पहुंचते हैं, इसके बाद समय पर निर्णय न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से जमानत मामलों में होने वाली देरी पर गहरी चिंता जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जमानत से जुड़े आदेश उसी दिन या अधिकतम अगले दिन तक जारी किए जाएं। इसके साथ ही, निचली अदालतों को भी निर्देश दिए गए हैं कि नियमित जमानत आदेशों की जानकारी

तुरंत संबंधित जेल प्रशासन तक पहुंचाई जाए, ताकि विचाराधीन कैदियों की रिहाई में अनावश्यक विलंब न हो।

पीठ ने माना कि कई बार जमानत मिलने के बावजूद तकनीकी और प्रशासनिक बाधाओं के कारण कैदियों को अतिरिक्त समय जेल में बिताना पड़ता है, जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी फैसलों को सुनाए जाने के 24 घंटे के भीतर संबंधित हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करें। हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि ये निर्देश किसी न्यायाधीश या न्यायिक संस्था पर सवाल उठाने के लिए नहीं हैं।

पम्मा के संघर्षों और सामाजिक कार्यों पर 10वां गाना जल्द होगा रिलीज

नई दिल्ली ।

'नेशनल अकाली दल' के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा के सामाजिक संघर्षों और जनहित के कार्यों पर आधारित 10वां गाना 'पम्मा बिना धरना सफल नहीं' जल्द रिलीज होने जा रहा है। इस गाने के बोल लिखे है प्रसिद्ध लेखक बलविंदर सिंह सोढ़ी ने जबकि इसे अपनी आवाज दी है गायिका रैश कौर ने। पम्मा पिछले 32 वर्षों से लगातार समाज और जनता के हितों के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। उनके कार्यों और संघर्षों को लेकर समय-समय पर कई प्रसिद्ध गायकों और लेखकों द्वारा गाने बनाए जा चुके हैं। उनके जीवन और सामाजिक आंदोलनों पर कई डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी हैं, जिन्हें काफी सराहा गया है।

बढ़ती महंगाई के खिलाफ आवाज उठानी हो, बच्चों की स्कूल फीस और कॉलेज दाखिलों की समस्याओं को लेकर संघर्ष करना हो, ऑनलाइन गेम्स से युवाओं और बच्चों के बिगड़ते भविष्य को लेकर सरकार को चेतावनी देनी हो या फिर महिलाओं और व्यापारियों के हितों की बात सरकार तक पहुंचानी हो, पम्मा हर मुद्दे पर सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं और सदैव आम जनता की आवाज बनकर सामने आए हैं। सामाजिक कार्यों के दौरान उन्हें कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा। लगातार संघर्षों और जन आंदोलनों के बीच उनके हार्ट में चार स्टंट तक पड़ चुके हैं लेकिन इसके बावजूद उन्होंने समाज सेवा और जनहित की आवाज उठाना कभी बंद नहीं किया। उनके इसी संघर्ष को रेखांकित करता यह नया गाना उनके संघर्ष, जज्बे और समाज के प्रति समर्पण को दर्शाएगा।

निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 की मौत

आंधी-बारिश के चलते हादसा, 3 मजदूरों को बचाया गया

हमीरपुर।

यूपी के हमीरपुर में बेतवा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का स्लैब शुक्रवार देर रात 2 बजे गिर गया। हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ने मलबे में फंसे 3 मजदूरों को निकाला। साढ़े 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉरपोरेशन के एमडी धर्मवीर सिंह ने बताया कि आंधी-बारिश के कारण स्लैब गिरा और नीचे सो रहे मजदूर दब गए। हादसे के बाद सहायक अभियंता गजेंद्र कुमार चौधरी को निलंबित कर दिया गया है। डीपीएम दिलीप कुमार पर विभागीय कार्रवाई शुरू की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, हमीरपुर में देर रात 70-80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली थी। हादसा शहर से 25 किमी. दूर ललपुरा इलाके में हुआ। मृतकों में 4 बांदा और 2 हमीरपुर के रहने वाले थे। एसडीआरएफ के अधिकारियों ने बताया कि रात छह बजे से शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। प्रत्यक्षदर्शी सुरेश कुमार ने बताया कि पुल पर दो शिफ्ट में काम होता है। जिस वक्त आंधी आई, पहली शिफ्ट के लोग पुल के नीचे थे, जबकि दूसरी शिफ्ट के 7 मजदूर पुल पर काम कर रहे थे। उनमें मैं भी था। आंधी से बचने के लिए हम लोग पुल पर लेट गए। इसी बीच हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम पुल का निर्माण करवा रहा है। इसकी लागत 90 करोड़ रुपए है। 700 मीटर लंबा दो लेन का ब्रिज मोरकांड से कुरारा गांव के बीच बनाया जा रहा है। इसका निर्माण मार्च 2024 में शुरू हुआ था। दिसंबर 2026 तक इसे पूरा किया जाना है।

मुठभेड़ में घायल बदमाश अस्पताल से फरार

करनाल।

करनाल में मेरठ रोड पर आवर्धन नहर के पास पुलिस मुठभेड़ में घायल शातिर बदमाश अस्पताल से फरार हो गया। बदमाश पर तरावड़ी के पेट्रोल पंप पर फायरिंग करने और लूट के प्रयास का मामला दर्ज था। घटना के 23 दिन बाद 25 मई को सीआईए-1 ने आरोपी को मुठभेड़ के दौरान काबू किया था। आरोपी को कूल्हे के पास टांग में गोली लगी थी। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल और बाइक भी बरामद की थी। घायल आरोपी को करनाल के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। यह शातिर अपराधी हरियाणा सहित देश के 5 अलग-अलग राज्यों की पुलिस के लिए पहले से ही मोस्ट वांटेड बना हुआ था। जहां पर उसका इलाज चल रहा था। इलाज के बाद आरोपी को पुलिस ने औपचारिक रूप से गिरफ्तार करना था और फिर कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेना था, जहां उससे गहनता से पूछताछ होनी थी। सरकारी अस्पताल के परिजनर वार्ड के बाहर 4 जवानों की गार्द लगी हुई थी, लेकिन बीती रात करीब 12 बजे आरोपी अस्पताल से फरार हो गया।

सुप्रीम कोर्ट ने विनेश को एशियन गेम्स के ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी

डब्ल्यूएफआई की याचिका खारिज

नई दिल्ली ।

सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवान विनेश फोगाफ को राहत देते हुए एशियन गेम्स के ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी विनेश के पक्ष में फैसला सुनाया था पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया(डब्ल्यूएफआई) उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गयी थी। इस मामले में शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डब्ल्यूएफआई की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। ऐसे में अब विनेश के गेम्स 2026 के ट्रायल्स में भाग लेने का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने कहा कि विनेश ने देश का सिर ऊंचा किया है। साथ ही कहा, अगर कोई और होता तो बात दूसरी होती। उसने देश को गर्व कराया है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने जिस तरह सुनवाई की, उस पर चिंता भी जताई पर उनके आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट ने जिस तरीके से इस मामले की सुनवाई की, वह ठीक नहीं है। अदालत ने चेताया कि खेल प्रशासन में अदालतों की जरुरत से ज्यादा दखलअंदाजी से स्पोर्टिंग इकोसिस्टम पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इससे पहले 22 मई को दिल्ली हाई कोर्ट की एक बेंच ने विनेश फोगाट को एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दे दी थी। अपने फैसले में हाई कोर्ट ने डब्ल्यूएफआई को फटकार लगाते हुए कहा था कि फेडरेशन की चयन नीति भेदभावपूर्ण थी क्योंकि मातृत्व अवकाश के बाद वापसी करने वाली उनकी नीति में दिग्गज खिलाड़ी पर विचार करने का उसमें कोई अधिकार नहीं था। हाई कोर्ट के इस फैसले को डब्ल्यूएफआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश दिया था कि फेडरेशन 30 और 31 मई को होने वाले चयन ट्रायल की वीडियो रिकॉर्डिंग कराये। इस दौरान भारतीय खेल प्राधिकरण (स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई) और भारतीय ओलिंपिक संघ का एक-एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक भी मौजूद रहे।

दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने आदेश दिया था कि विनेश एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में हिस्सा लेंगी। अदालत ने डब्ल्यूएफआई के इस रवैये पर भी नाराजगी जताई कि उसने कारण बताओ नोटिस में फोगाट के 2024 पेरिस ओलिंपिक खेलों से बाहर होने को राष्ट्रीय शर्मिंदगी बताया था।

सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू

बेंगलुरु।

कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया शुक्रवार को दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां कांग्रेस आलाकमान के साथ उनकी एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। खराब मौसम के कारण उनका विमान पहले जयपुर डायवर्ट किया गया था, जिसके बाद वे दिल्ली पहुंचे। राज्यपाल थावर चंद गहलोत उनका इस्तीफा पहले ही स्वीकार कर चुके हैं और नई व्यवस्था होने तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभालने को कहा गया है। इसी बीच राज्य के प्रमुख नेता डीके शिवकुमार भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिससे कांग्रेस के भीतर नए नेतृत्व और सत्ता के बदलाव को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं।

सूत्रों के अनुसार, दिल्ली में सिद्धारमैया, रणदीप सिंह सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल

की राहुल गांधी के साथ अहम मुलाकात होने जा रही है। इसके साथ ही डीके शिवकुमार भी कांग्रेस हाईकमान से मिलेंगे, हालांकि उनकी बैठक का समय अभी पूरी तरह तय नहीं हुआ है। इस्तीफे के बाद सिद्धारमैया कर्नाटक भवन में रुकने के बजाय दिल्ली में एक निजी स्थान पर ठहरे हुए हैं। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अब राज्य में नए सत्ता संतुलन और विभिन्न जातीय समीकरणों को साधने की गंभीर कोशिशों में जुटा है। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच शनिवार को बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने की पूरी संभावना है, जहां नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। पार्टी के भीतर नए मुख्यमंत्री के रूप में डीके शिवकुमार के नाम की लगातार चर्चा हो रही है, जबकि सिद्धारमैया की भविष्य में क्या भूमिका होगी, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस अब राज्य के प्रमुख लिंगायत समुदाय और अहिंदा यानी पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलित वोट बैंक के बीच एक मजबूत संतुलन बनाते हुए अपनी आगे की रणनीति तय करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ को दिया बड़ा झटका

विनेश फोगाट मैट पर लौटेंगी

नई दिल्ली।

भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2026 एशियन गेम्स के चयन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी। ये ट्रायल्स 30 और 31 मई को आयोजित होने हैं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसे भारतीय कुश्ती महासंघ ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर किया था। हाईकोर्ट ने पहले ही विनेश फोगाट को ट्रायल्स में भाग लेने की इजाजत दी थी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि विनेश फोगाट का मामला सामान्य खिलाड़ियों से अलग है, क्योंकि उन्होंने देश को कई मौकों पर गौरवान्वित किया है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई और खिलाड़ी होता तो मामला अलग होता। उन्होंने देश का नाम रोशन किया है. हालांकि, कोर्ट ने खेल मामलों में बार-बार न्यायिक हस्तक्षेप को लेकर चिंता भी जताई। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि आप शानदार रेसलर हैं, आपने देश को गर्व महसूस कराया है, लेकिन देश पहले है. हाईकोर्ट पूरे शेड्यूल को बाधित नहीं कर सकता।सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के तरीके पर भी सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि खेल प्रशासन में इस तरह तेजी से हस्तक्षेप करने से पूरे स्पोर्ट्स सिस्टम और शेड्यूल पर असर पड़ सकता है।

महाराष्ट्र में जहरीली शराब से 15 की मौत, 8 आरोपी गिरफ्तार

सीएम ने कहा, पूरे इकोसिस्टम की कमर तोड़ दी जाएगी

पुणे ।

महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ इलाकों में जहरीली शराब पीने से करीब 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे हैं। इस भयावह घटना के बाद राज्य और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले पर संज्ञान लेकर 8 संदिग्ध आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि कर बताया है कि पूरे अवैध शराब के इकोसिस्टम का पता लग गया है, जिस पर आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह चौंकाने वाली घटना पुणे के काले पड़ल, हडपसर और पिंपरी-चिंचवाड़ के दापोडी, फुगेवाड़ी जैसे इलाकों से सामने आई है, जहां लोगों ने अवैध रूप से निर्मित जहरीली शराब का सेवन किया। जानकारी के अनुसार, जहरीली शराब का सेवन करने वाले लोगों की हालत अचानक बिगड़ी, उनके मुंह से झाग निकलने लगा और इलाज मिलने से पहले ही कई लोगों ने दम तोड़ दिया। पिंपरी-चिंचवाड़ के दापोडी और फुगेवाड़ी में आठ, जबकि पुणे के काले पड़ल में तीन और हडपसर में दो लोगों की मौत हुई।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस अवैध और स्पिरिट-युक्त शराब को योगेश वानखेड़े नामक व्यक्ति ने तैयार किया था, इस जहरीली शराब को पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ के विभिन्न इलाकों में बेचा गया था। वानखेड़े कथित तौर पर अवैध शराब कारोबार से जुड़ा है और उसके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े का गिरफ्तार किया है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने मामले की गंभीरता को देखकर पुलिस को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि मामले में अभी तक 8 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पूरे अवैध शराब के इकोसिस्टम का पता लग गया है, इसके बाद इस पूरे इकोसिस्टम की कमर तोड़ दी जाएगी। पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस के डीसीपी संदीप अटोले ने पुष्टि की है कि सात लोगों की मौत हुई है और तीन घायल अस्पताल में उपचाराधीन हैं, जबकि आठ आरोपियों से पूछताछ जारी है।

लोकल नागरिकों में फुगेवाड़ी जैसे इलाकों में अवैध हाथभट्टी और देशी शराब के अड्डों के धड़ल्ले से चलने को लेकर भारी आक्रोश

है। हालांकि, शुरुआत में दापोडी पुलिस ने जहरीली शराब से हुई मौतों की बात को अफवाह बताकर दावा किया था कि ये सभी मौतें अलग-अलग और स्वतंत्र कारणों से हुई हैं। यह बयान पुलिस की जांच पर सवाल खड़े करता है, खासकर तब जब मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्वयं इकोसिस्टम की पहचान और गिरफ्तारी की बात कही है। पुलिस अब मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है और घायलों का इलाज जारी है।

नैनीताल जाने बस में भारी भीड़, सीट पाने खिड़कियों से अंदर घुसे पर्यटक

हल्द्वानी। नैनीताल जाने वाली बसों में भीड़ देखने को मिल रही है। रोडवेज स्टेशन में बस आते ही लोग खिड़कियों से अंदर घुसने लगे। अन्य दिनों में जहां आठ बसें नैनीताल के लिए चलती थीं तो वहीं गुरुवार को नौ बसें नैनीताल गईं। सभी बसों ने दो से तीन फेरे नैनीताल रूट के लगाए। गुरुवार को बकरीद होने पर छुट्टी का दिन होने से हल्द्वानी रोडवेज में नैनीताल घूमने के लिए रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर व यूपी के पर्यटक उमड़ पड़े। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक काठगोदाम से ऊपर पुलिस ने बेवजह घूमने वाले दोपहिया व टैक्सी वाहकों पर बैन लगा दिया था। दोपहिया वाहन में सवार होकर पर्वतीय रूटों को सिर्फ स्थानीय लोगों को ही जाने दिया जा रहा था। शुक्रवार से पर्वतीय रूटों में भीड़ बढ़ने का अनुमान है। इधर, हल्द्वानी बस स्टेशन के एआरएम ने बताया कि दिल्ली के लिए काफी कम बसें ही जा सकें। दिल्ली जाने के लिए शुक्रवार को सवारी नहीं मिली। नैनीताल रूट पर सवारियां गईं हैं। वहीं काठगोदाम डिपो के एआरएम ने बताया कि नैनीताल रूट के लिए 10 बसें भेजी गईं थी।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक कजोड़मल मीना के लिए स्काईटक प्रिन्टर्स, 111, नवाब कल्लन का बाग, एमएलए क्वार्टर, नीयर समाचार जगत, एमआई रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 303, भव्य टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर से प्रकाशित।
(इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी) समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर शहर होगा। RNI No. RAJHIN/2001/05699 मो. नं. 9928078717